

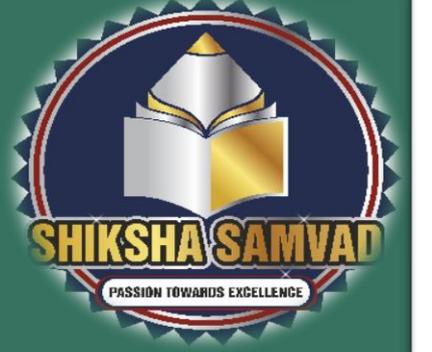
SHIKSHA SAMVAD

International Open Access Peer-Reviewed & Refereed
Journal of Multidisciplinary Research

ISSN: 2584-0983 (Online)

Volume-1, Issue-2, Oct-Dec- 2023

www.shikshasamvad.com



वर्तमान भारत में राजा राममोहन राय के शिक्षा-दर्शन की प्रासंगिकता एवं उपादेयता

डॉ. स्वाति प्रिया

सहायक प्राध्यापक

न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ एजुकेशन
सिमरिया, टीएमबीयू, भागलपुर, बिहार

सारांश:

वर्तमान भारत में राजा राममोहन राय के शिक्षा-दर्शन का अध्ययन करने से प्रासंगिकता और उपादेयता की महत्वपूर्ण पहलुओं का समर्थन मिलता है। उनका शिक्षा-दर्शन समृद्धि और सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में उत्कृष्ट था। राय ने विद्या को समाज के सर्वोत्तम निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना और उसे समर्पित और सुसंस्कृत समाज की श्रेष्ठता की दिशा में उत्तेजना की।

राजा राममोहन राय ने सामाजिक अधिकार और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, जिससे उनके शिक्षा-दर्शन ने एक सामरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध समाज की आवश्यकता को प्रमोट किया। उन्होंने नई विद्यार्थियों के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थानों की नींव रखी और विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में शिक्षित करने के लिए अधिक विस्तारपूर्ण शिक्षा-कार्यक्रमों का समर्थन किया।

राजा राममोहन राय के शिक्षा-दर्शन ने भारतीय समाज को उदार और प्रगतिशील सोच की दिशा में प्रेरित किया, जिससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली को मिला समर्थन और उत्कृष्टता का मार्ग प्रदान हुआ। उनके शिक्षा-दर्शन का महत्वपूर्ण संदेश है कि शिक्षा समाज के समृद्धि और समरसता के लिए एक कुशल और संरचनात्मक उपाय है, जो सामाजिक न्याय और समानता की प्रेरणा को प्रोत्साहित करता है।

मुख्य शब्द : शिक्षा-दर्शन, शिक्षा, सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक न्याय, आदि ।

भारत में आधुनिक शिक्षा की पहल:

राममोहन के जन्म के समय अर्थात् जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में प्रशासनिक पैर जमाना आरम्भ कर दिया, उस अराजक राजनैतिक और सामाजिक परिस्थिति में, देश में शिक्षा की स्थिति कैसी रही होगी, कल्पना करना बहुत ही कठिन नहीं है। उस काल में शिक्षा बहुत ही सीमित वर्ग को ही उपलब्ध थी। गाँवों में कुछ पाठशाला या टोल थे, जहाँ संस्कृत शिक्षा दी जाती थी और मस्जिदों से संलग्न मदरसों या मकतबों में अरबी-फारसी में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत के उच्च अध्ययन के

लिए उत्तर भारत में वाराणसी, उज्जैन जैसे केन्द्र थे तो अरबी-फारसी के केन्द्र पटना, रामपुर, दिल्ली आदि नगर थे। जनशिक्षा या साक्षरता को कोई भी प्रयास इस काल में होना सम्भव नहीं था। छापेखाने की स्थापना इसी काल में भारत की भूमि पर पहले-पहल आरम्भ हुई। फारसी अभी तक राजभाषा थी। यद्यपि भारत में अंग्रेजी शासन को पचास वर्ष हो रहे थे, लेकिन प्रशासन और अदालत का काम मुगलकालीन तौर तरीके से चल रहा था। इसी कारण अरबी-फारसी और उर्दू शिक्षा की ओर अभिजात या सम्पन्न वर्ग का ध्यान था। फारसी शिक्षा के लिए राममोहन को बचपन से पटना भेज दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में यह महसूस किया गया कि इस्लाम धर्म और शास्त्रों के पठन-पाठन के लिए और अरबी-फारसी और उर्दू के उन्नयन के लिए कलकत्ता में कोई विद्यालय नहीं है। इसी से हेस्टिंग्स ने 1780 में कलकत्ता 'मदरसा' की स्थापना की।

इस प्रकार देखा जाए तो संस्कृत और अरबी-फारसी की शिक्षा, कई शताब्दियों से सीमित स्वार्थ के लिए सीमित वर्ग तक ही नियन्त्रित थी। स्वार्थ या प्रशासकीय और धार्मिक ठेकेदारी आज के युग में जिसे जनशिक्षा की संज्ञा दी जाती है, यह विचार उस समय तक लोगों के ध्यान में आया ही न था। इस समय देश में यूरोपीय लोगों के आगमन का, चाहे जो भी अर्थनैतिक और राजनैतिक कारण रहा हो, देश में शिक्षा के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका बनी। वस्तुतः साधारण जनता की शिक्षा की ओर सबसे पहले ध्यान यूरोपीय ईसाई मिशनरियों का गया। उन्हीं लोगों ने सबसे पहले शिक्षा विस्तार के लिए स्कूल खोले, छापाखाने का प्रयोग करने और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन की ओर ध्यान दिया। यह एक सर्वभारतीय घटना थी। मुख्य उद्देश्य यद्यपि ईसाई धर्म का प्रचार ही था। बंगाल क्षेत्र में विलियम केरी इस कार्य में अगुवा थे। भारत में आते ही उन्होंने मालदह के मदनबाटी गाँव में, जहाँ नील काश्तकारों की कोठियाँ थीं, वहाँ उन्होंने गाँव के लोगों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। विद्यालय के छात्रों के लिए उन्होंने न्यू टेस्टामेण्ट का अनुवाद भी आरम्भ किया। मदनबाटी से अपने छापेखाने के साथ केरी, श्रीरामपुर रेवरेण्ड मार्शमैन के पास आ गये। सन् 1800 में उन्होंने श्रीरामपुर में पहला देशी स्कूल खोला और शिक्षा का माध्यम बांग्ला भाषा ही बनाया। केवल इतना ही नहीं भाषा को शुद्ध और परिष्कृत करके आधुनिक रूप देने का प्रथम प्रयास भी इन ईसाई पादरियों ने ही किया। इस इतिहास से आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य के ज्ञाता परिचित हैं। मालदह के मदनबाटी से पूरे छापेखाने को श्रीरामपुर ले आना और बैप्टिस्ट मिशन प्रेस की स्थापना आदि का भी एक अलग इतिहास है। इसी बीच संस्कृत साहित्य के कुछ यूरोपीय प्राच्यविदों की प्रचेष्टा से, जिनमें प्रख्यात सर विलियम जोन्स भी थे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हो चुकी थी। प्राच्यविद् जॉनाथन उन्कन, जो बनारस के रेजिडेन्ट थे, के प्रयास से 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में मदरसा और बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना के पीछे देश शासन के लिए उपयुक्त शासक वर्ग को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षित करना।

था। हो, इन प्रयासों से संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति के पूनर्मूल्यांकन की ओर ध्यान अवश्य गया। सन् 1800 में लार्ड वेलेजली द्वारा यूरोपीय प्रशासकों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना भी एक महत्त्वपूर्ण घटना थी, यद्यपि यह कालेज केवल मात्र ब्रिटिश शासकों को प्रशिक्षित करने के लिए, स्थापित किया गया था, फिर भी इस संस्था के पण्डितों और मौलवियों ने बांग्ला, हिन्दी और उर्दू भाषाओं के आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक अध्ययन में जो भूमिका निभाई, वह भाषा और साहित्य के इतिहासकारों से छिपी नहीं है।

भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सम्भावनाओं के बारे में पहली सुचिन्तित टिप्पणी, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एक वरिष्ठ अधिकारी चार्ल्स ग्रान्ट ने 1792 में पेश की थी। इस टिप्पणी में सिफारिश की गई थी कि यूरोपीय विज्ञान और साहित्य भारत में अंग्रेजी माध्यम से परिवर्तित किया

जाए, क्योंकि उनकी धारणा थी कि इस पद्धति से मानसिक दासता की जंजीरे टूटेगी। तकनीकी ज्ञान और मशीन के प्रवर्तन से, साधारण जनता की औद्योगिक अभिरूचि बढ़ेगी और मानसिक जड़ता से मुक्त होकर वे सक्रिय हो उठेंगे। देश की शक्ति ही बदल जायेगी। उस समय ग्रान्ट साहब के विचार कम्पनी के प्रभुओं को आवश्यकता से अधिक प्रगतिशील लगे। ग्रान्ट साहब के विचारों से प्रभावित होकर सन् 1793 में मि. विलबरफोर्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि यह ब्रिटिश सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि विवेकपूर्ण साधनों के द्वारा भारत में ब्रिटिश 'अधिकार क्षेत्र में लोगों की भलाई और खुशहाली के लिए कदम उठाये जाए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे उपाय किए जाए, जो उपयोगी ज्ञान-विज्ञान के साथ धार्मिक और नैतिक उन्नति में सहायक हों। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1813 के चार्टर-एक्ट में व्यवस्था की गई और ऐसे लोगों को, जो देसी लोगों में शिक्षा धर्म और नैतिकता का प्रचार करना चाहे भारत जाने की अनुमति दी गई ।

सन् 1811 में लार्ड मिन्टो के प्रशासकीय विवरण में भारत में शिक्षा की स्थिति के बारे में बहुत ही निराशाजनक छवि प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था कि विज्ञान और साहित्य दोनों ही अपक्षय की स्थिति में पहुँच चुके हैं। धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त और किसी प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण एक प्रकार से बन्द है। अनेक उपयोगी ग्रन्थ व्यवहार न होने के कारण नष्ट हो रहे हैं। यदि सरकार इस ओर अपना हाथ नहीं बढ़ायेगी तो साहित्य और शिक्षा, पुस्तकों और अध्यापकों के अभाव में पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इससे पहले राजे-महाराजे, नवाब आदि शिक्षा और विद्वता को संरक्षण दिया करते थे। विद्वानों और साहित्यकारों के लिए और कोई सहारा नहीं था। अब क्योंकि इस प्रकार का संरक्षण भी नहीं रहा, इसी से ज्ञान-विज्ञान की चर्चा धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। लार्ड मिन्टो के विचार से उचित शिक्षा का अभाव ही इस देश के लोगों की अवनति का मुख्य कारण था और एक अच्छे शासन के प्रवर्तन में भी बाधा है, क्योंकि नैतिक और धार्मिक शिक्षा की भी पूरी व्यवस्था नहीं है, इसी से लोग दुराचारी हो गए हैं। अपराधों के लिए अज्ञानता ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। टिप्पणी में उन्होंने आगे लिखा कि इसीलिए आवश्यक है कि कुछ धनराशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जाए, जिससे ज्ञान-विज्ञान और शिक्षा कार्य को फिर से प्रतिष्ठित किया जा सके। उन्होंने बनारस के संस्कृत कालेज के सुधार के लिए सिफारिश की। साथ ही नदिया और तिरहुत में नए विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। ऐसे ही विद्यालय भागलपुर और जौनपुर में भी स्थापित करने का सुझाव दिया। लार्ड मिन्टो के इस महत्त्वपूर्ण टिप्पणी के बावजूद इस ओर कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

सन् 1813 के ईस्ट इण्डिया एक्ट की धारा में पहले पहल शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी को स्वीकार किया गया और एक लाख रुपये की निर्धारित राशि प्रतिवर्ष साहित्य और शिक्षित वर्ग को उत्साहित करने और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया।

सन् 1815 में लार्ड मोइरा ने कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के समक्ष शिक्षा सम्बन्धी एक टिप्पणी पेश की। इस टिप्पणी में नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया।

इधर इन शिक्षा सम्बन्धी वाद-विवाद और कागज़ी कार्यवाही के अलावा सरकार की ओर से कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया। जो धनराशि शिक्षा के खाते में प्रतिवर्ष रखी जाती, उसका भी कोई व्यवहार नहीं किया गया। आगे चलकर 1824 में जब कलकत्ते में संस्कृत कालेज की स्थापना हुई तो इस धन का इस्तेमाल किया गया।

इसी बीच सन् 1817 में कलकत्ता में हिन्दू कालेज, श्रीरामपुर में बैप्टिस्ट मिशन कालेज, और सन् 1820 में कलकत्ता में बिशप कालेज की स्थापना गैर सरकारी क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा के आरम्भिक केन्द्र थे। इसके अतिरिक्त अँग्रेज़ी शिक्षा के लिए कुछ स्कूलों की शुरुआत

भी इसी काल में हुई। सन् 1818 में सरकारी सहायता से 'स्कूल बुक सोसाइटी' नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ी और बांग्ला भाषा में स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों की रचना और प्रकाशन। इधर साधारण जनता में अंग्रेज़ी सीखने का आग्रह बढ़ता जा रहा था। विद्यालयों की भारी कमी थी। कलकत्ते में जगह-जगह नये-नये अंग्रेज़ी स्कूलों की स्थापना होने लगी। 1818 में कैलकटा स्कूल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था नये विद्यालयों की स्थापना में सहायता देना। ये सारे ही गैर-सरकारी प्रयास थे। इसमें डेविड हेयर का नाम प्रमुख था। अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों की स्थापना में उनका उत्साह, सहयोग और परिश्रम सर्वविदित है। इसी काल में बांग्ला और हिन्दी भाषा अपने आधुनिक रूप में विकास के पथ पर बढ़ रहे थे। मिशनरी लोग केवल बाइबिल का अनुवाद करके धर्म प्रचार कर रहे थे। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों की रचना और अंग्रेज़ी से अनुवाद करने में इन्हीं लोगों ने पहल की। परिस्थितियों के बावजूद अंग्रेज़ी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार और प्रसार के बारे में मत विरोध चल रहा था। सरकारी अमले के अधिकारी अब भी पारम्परिक शिक्षा अर्थात् संस्कृत और अरबी-फारसी शिक्षा के पक्ष में थे। वस्तुतः इस काल में दो विरोधी पक्ष आमने-सामने आ गये। एक दल, जिनमें प्रसिद्ध प्राच्यविद् सम्मिलित थे, संस्कृत और अरबी-फारसी की शिक्षा के पक्ष में थे तो दूसरी ओर राममोहन राय का दल था, जो अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रवर्तन के पक्ष में थे। स्कूल, हिन्दू कॉलेज की स्थापना और राममोहन की भूमिका के बारे में जीवनी वाले प्रथम अध्याय में विस्तार से लिखा जा चुका है। इसके अलावा एंग्लो हिन्दू स्कूल की स्थापना का इतिहास हम कर चुके हैं। यह भी देख चुके हैं कि राममोहन ने विलायत रवाना होने से पूर्व डफ साहब को विलायत से बुलवाकर उन्हें पूरी तरह कलकत्ते में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। डफ साहब के स्कूल के लिए घर-घर घूम कर उन्होंने विद्यार्थी इकट्ठे किए और स्कूल के लिए मकान का इन्तजाम किया। राममोहन ने सोचा था अंग्रेज़ी शिक्षा ही देश की उन्नति में सहायक होगी।

सन् 1823 में तत्कालीन सचिव श्री होल्ट मैकेंजी ने, जो शिक्षा विभाग भी सम्हालते थे, शिक्षा के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आदर्श शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। शिक्षा के उद्देश्यों और सरकार की जिम्मेदारी के बारे में लिखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के लोगों की खुशहाली और नैतिक उन्नति की जिम्मेवारी सरकार की है। उन्होंने प्राच्य विद्या और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान दोनों प्रकार की शिक्षा देने की सिफारिश की। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षण संस्थाओं में उच्च शिक्षित व्यक्ति रखे जाएँ और नई शिक्षण संस्थाओं में पूर्वी और पाश्चात्य विद्या को साथ-साथ पढ़ाया जाए। मैकेंजी साहब ने यहाँ तक सिफारिश की कि प्रस्तावित संस्कृत कालेज में भी विज्ञान-शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मैकेंजी साहब की टिप्पणी में शिक्षा सम्बन्धी कुछ नई बातें देखने में आईं। पहली बार एक आदर्श और आधुनिक शिक्षा नीति का स्वरूप सामने आया। प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति के समन्वय की बात भी कही गई, जिससे उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी तक सभी को साथ लाने की बात सोची गई। इसके अलावा प्राच्य विद्या और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा अंग्रेज़ी के माध्यम से देने का प्रस्ताव भी आया। लेकिन इन विचारों को प्रयोग में लाने के लिए अभी दस बारह वर्ष इन्तजार करना पड़ा, जब मैकाले ने 1835 में अंग्रेज़ी शिक्षा पर अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी प्रस्तुत की, जो भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तन में मील का पत्थर बनी।

जुलाई सन् 1823 को लार्ड अमहर्स्ट के जमाने में शिक्षा सम्बन्धी एक कमेटी नियुक्त की गई। उद्देश्य था, देश के इस भाग में शिक्षा सम्बन्धी स्थिति का जायजा लेना और शिक्षा की उन्नति के बारे में नए सुझाव देना। साथ ही, इस कमेटी को सारी सरकारी शिक्षण संस्थाओं की देख-रेख करने का अधिकार दिया गया। इस कमेटी की सिफारिश पर यह तय पाया गया कि उपलब्ध धन से पहले कलकत्ते में एक कालेज

की स्थापना की जाये, जहाँ हिन्दू धर्मशास्त्रों का पठन-पाठन हो। यद्यपि यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का सुझाव भी सामने आया, लेकिन कुछ यूरोपीय प्राच्यविदों, जिनमें विलसन जैसे विद्वान भी थे, के आग्रह पर संस्कृत कालेज की स्थापना का प्रस्ताव पास हो गया। यह एक अजीब विडम्बना थी कि यूरोपीय सदस्यों की कमेटी ने यूरोपीय और अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध राय दी और संस्कृत और हिन्दू धर्मशास्त्रों के पठन-पाठन का समर्थन किया।

राममोहन ने लार्ड अमहर्स्ट को 11 दिसम्बर, 1823 को शिक्षा के विषय में जो प्रसिद्ध पत्र लिखा था, उसकी पृष्ठभूमि का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। इन परिस्थितियों में जहाँ राममोहन अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तन के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे, उनके लिए सरकार की ओर से संस्कृत विद्यालय की स्थापना एक निराशाजनक घटना थी। उस काल में भारत में तो क्या यूरोप में भी अभी तक विज्ञान-शिक्षा को वह स्थान प्राप्त नहीं था। उस समय राममोहन ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैज्ञानिक शिक्षा के बिना देश की उन्नति असम्भव है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी आशा थी कि यह धन यूरोपीय विद्वानों की नियुक्ति में खर्च किया जायेगा और देश में गणित, विज्ञान, रसायन, शरीर विद्या और दूसरे उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा दी जायेगी। संस्कृत शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग पिछले दो हजार सालों से संस्कृत ही सीखते आये हैं। अब इस विद्या को सीखने से भला क्या लाभ हो सकता है? सरकार ने धन का प्रावधान प्रजा की भलाई के लिए किया था, युवकों के संस्कृत शिक्षा के पीछे समय नष्ट करने से देश का क्या भला हो सकता है? उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि संस्कृत को बढ़ावा देना ही हो तो विद्यमान संस्कृत विद्यालयों को कुछ आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

हम अच्छी तरह जानते हैं कि राममोहन स्वयं संस्कृत के पण्डित थे और धार्मिक भावना उनमें सर्वोपरि थी। उनके धर्मविषयक शास्त्रार्थ और लेखों से यह भी स्पष्ट है कि उन्हें संस्कृत और अपनी संस्कृति से गहरा लगाव था। लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी पूरा विश्वास था कि देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है।

राममोहन के इस पत्र में वस्तुतः दो परस्पर विरोधी शिक्षा पद्धतियों की तुलना की गई थी। एक पक्ष था मध्ययुगीन भारतीय पद्धति का और दूसरा आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का। उन्होंने आधुनिक विद्यालयों में मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त प्राचीन पद्धति पर चलने वाले संस्कृत और अरबी-फारसी की शिक्षा देने वाले संस्थाओं की देश में कमी नहीं थी। कमी थी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की।

निष्कर्ष:

वर्तमान भारत में राजा राममोहन राय के शिक्षा-दर्शन का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि उनकी शिक्षा-दर्शन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बुनियाद रखने में कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने शिक्षा को समाज के समृद्धि और समरसता के लिए एक आधारभूत साधन माना और उसे सामर्थ्यपूर्ण और सुसंस्कृत समाज की दिशा में उत्तेजना की। राजा राममोहन राय ने सामाजिक अधिकार और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और उनके शिक्षा-दर्शन ने विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए व्यापक योजनाएं प्रोत्साहित की। उनके दर्शन ने भारतीय समाज को उदार और प्रगतिशील सोच की दिशा में प्रेरित किया, जिससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप, राजा राममोहन राय के शिक्षा-दर्शन ने भारतीय समाज को एक उच्च स्तरीय और समृद्ध समाज की दिशा में प्रेरित किया है।

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

1. अरविन्द पोद्दार ए राममोहन उतरपक्ष ए कलकत्ता उच्चारण ए 1982
2. क्षितिमोहन सेन ए युगगुरू राममोहन कलकत्ता 1952
3. मणि बागची ए राममोहन कलकत्ता जिज्ञासा 1958
4. ताराचन्द हिस्टी ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इण्डिया वाल्यूम प्रथम एवं द्वितीय
5. एण्ड्रूज सी0एफ0 इण्डियन रेनेसां



SHIKSHA SAMVAD



An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2584-0983 (Online)

Volume-01, Issue-02, Oct-Dec- 2023

www.shikshasamvad.com

Certificate Number-Dec-2023/21

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. स्वाति प्रिया

For publication of research paper title

**“वर्तमान भारत में राजा राममोहन राय के शिक्षा-दर्शन की प्रासंगिकता एवं
उपादेयता”**

Published in ‘Shiksha Samvad’ Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and
E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-01, Issue-02, Month December, Year- 2023.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper
must be available online at www.shikshasamvad.com